

## भारत और इजरायल संबंध : सुरक्षा एवं कूटनीतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से एक विश्लेषणात्मक अध्ययन



**अनिषा जोशी, प्रीति अग्रवाल**

सहायक आचार्य, मांडिया कॉलेज,  
नीमकाथाना, सीकर



**प्रीति अग्रवाल**

सहायक आचार्य, मांडिया कॉलेज  
नीमकाथाना, सीकर

**DECLARATION:** I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. . IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL.

### शोध पत्र की संक्षिप्तिका –

जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था। उससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल की जमीन पर कदम नहीं रखा था। मोदी की वह लीक तोड़ने वाली यात्रा थी। इसलिए इस दौरे को भारत-इजरायल दोस्ती में मील का पत्थर माना गया। भारत के प्रधान मंत्री की इजरायल यात्रा के दौरान दोनो देशों के बीच सामरिक व कूटनीतिक भागीदारी स्थापित करने पर सहमति बनी थी। दोनो देशों के रणनीतिक हितों की रक्षा करने की बात करते हुए भारत और इजरायल एक ऐसे जटिल भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ दोनो के सामने क्षेत्रीय शान्ति एवं स्थायित्व को लेकर सदैव खतरा बना रहता है। ऐसे में दोनो देशों ने अपने सामरिक हितों की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए साइबर स्पेस के साथ-साथ आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ साझा जंग का ऐलान किया है। इन्हीं चुनौतियों को मध्य नजर रखते हुए भारत ने इजरायल की रक्षा कंपनियों को 'मेक इन इंडिया' में संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इजरायल के लिए निवेश के अच्छे अवसर हैं। अतः दोनो देशों के सहयोग में वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएँ छिपी हुई हैं। स्पष्ट है कि पूर्णकालिक कूटनीतिक संबंधों की रजत जयंती वर्ष मना रहे। इन दोनो देशों में संबंध प्रगाढ़ता और परिपक्वता की दिशा में अग्रसर हैं।

## परिचय –

इजरायल के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों की उम्र यों तो 25 साल पुरानी है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और तत्पश्चात नेतन्याहू के दौर ने रिश्तों का एक नया क्षितिज खोल दिया है। 1947 से लेकर 1992 के बीच भारत के द्वारा फिलीस्तीन का लगातार समर्थन किया गया और फिलीस्तीन की समस्या के समाधान के लिए भारत ने द्वि-राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन किया। शीतयुद्ध के दौरान अनेक मुद्दों पर अरब देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विदेश नीति का समर्थन नहीं किया तथा सदैव पाकिस्तान का साथ दिया। इसके पश्चात भारत ने इजरायल के प्रति अपनी परम्परागत नीति पर पुनर्विचार किया। 1992 में भारतीय विदेश नीति में निर्णायक परिवर्तन हुआ जिसके अनुसार भारत ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध बना लिये। वर्ष 2012 में एस.एम. कृष्णा ने इजरायल की यात्रा की तथा इजरायल ने भारत को 'प्राकृतिक मित्र' की उपमा दी। 1992 के बाद भी भारत के द्वारा फिलीस्तीन को दिया गया समर्थन बना रहा परन्तु इजरायल के साथ समानान्तर संबंधों का विकास किया गया।

## शोध का महत्व व प्रासंगिकता –

“भारत और इजरायल संबंध : सुरक्षा एवं कूटनीतिक दृष्टि से एक विश्लेषणात्मक अध्ययन” संबंधी विषय शोध का अपना महत्व है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इजरायल भारत के लोकतंत्र के प्रति सम्मान का भाव रखता है। वर्ष 1948 में भारत ने इजरायल को मान्यता प्रदान कर दिया लेकिन इजरायल के साथ भारत ने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना नहीं की। इसके विपरीत इजरायल ने वर्ष 1962 में भारत-चीन के युद्ध तथा वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध में भारत का समर्थन किया। सभी अरब राज्यों ने भारत का कश्मीर मामले पर समर्थन नहीं किया लेकिन भारत ने अरब राज्यों का फिलीस्तीन के मुद्दे पर सदैव समर्थन किया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रक्षा आपूर्ति के लिये भारत ने इजरायल के महत्व को स्वीकार किया क्योंकि इजरायल रक्षा सामग्री का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। इसलिए अब भारतीय विदेश नीति में “समान दूरी का सिद्धान्त” अपनाया गया। फिलीस्तीन मुद्दे पर समर्थन देने के साथ इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किये गये। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इजरायल ने सदैव भारत का साथ दिया है। इस प्रकार भारत-इजरायल दोनों ही राष्ट्रों ने एक दूसरे के महत्व को समझा और यह संबंध आगे की ओर बढ़ता गया। इसलिए भारत-इजरायल संबंध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है।

### प्रस्तावित शोध का उद्देश्य –

- भारत और इजरायल के सामरिक व कूटनीतिक संबंधों का विश्लेषण करना इस शोध का उद्देश्य है।
- भारत और इजरायल दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी संगठन गंभीर खतरे हैं। इसलिए सीमा प्रबन्धन व क्षेत्रीय शांति स्थापना जैसी चुनौतियों को इंगित करना इस लेख का उद्देश्य है।
- दोनों देशों के दीर्घकालीन सहयोग के साथ-साथ नवाचार व विकास की संभावनाएँ तलाशना भी इस लेख का उद्देश्य है।
- सामरिक व कूटनीतिक दृष्टि से भारत-इजरायल सहयोग की महत्वता बतलाना भी इस लेख का उद्देश्य है।
- भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इजरायल के लिए निवेश के अच्छे अवसर हैं। इजरायल यदि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश करता है तो इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी। निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना भी इस शोध का उद्देश्य है।

### इजरायल व राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य –

- इजरायल कृषि तकनीक व राजस्थान कृषि प्रणाली दोनों में भौगोलिक दृष्टिकोण से समानता है। जैसे जलवायु, धरातल, रेगिस्तानी क्षेत्र, पानी की न्यूनता व वर्षा का अभाव।
- सर्वप्रथम राजस्थान में फव्वारा पद्धति इजरायल की देन है।
- भारतीय कृषि व्यवस्था में इजरायल कृषि तकनीक का बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग रहा है।

### शोध की पद्धति –

शोध अध्ययन उद्देश्य के आधार पर अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण शोध की अनेक प्रविधियाँ शोध के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों की सहायता ली गई है। स्रोतों के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख तथा अन्य

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख आदि का अध्ययन किया गया है। चूंकि अध्ययन की विषय-वस्तु समसामयिक है इसलिए इन्टरनेट से भी तथ्यों का संकलन किया गया है। विभिन्न वेबसाइट, गूगल स्कॉलर तथा शोधगंगा जैसे मंचों से भी विषय-वस्तु का संकलन किया गया है।

अध्ययन में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का सैद्धान्तिक एवं अधिकतम व्यावहारिक लेकिन निरपेक्ष मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। शोध की पद्धति वर्णात्मक तथा विश्लेषणात्मक है। अध्ययन पूर्वाग्रह से मुक्त एवं विवेक सम्मत विश्लेषण पर आधारित है।

### शोध की परिकल्पना –

वैज्ञानिक अध्ययन में परिकल्पनाओं का निर्माण बहुत आवश्यक है। परिकल्पना के द्वारा शोध की दिशा निर्धारित होती है। अन्त में यह कहना गलत नहीं होगा कि परिकल्पना एक शोधकर्ता को सत्य खोजने के कार्य में सहायक सिद्ध होती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने अपने शोधपत्र के निर्मित जिन परिकल्पनाओं का निर्माण किया है वे निम्नलिखित हैं –

- राजस्थान जैसे विषम परिस्थिति वाले राज्य में इजरायल कृषि तकनीकियों, यंत्रीकरण, आधुनिक नवाचार का भी समय-समय पर व्यापक स्तर पर भविष्यता को मध्यनजर रखते हुये आगामी कुछ वर्षों में इनके दुरगामी परिणाम अत्यधिक लाभदायक तथा पर्यावरण सतत विकास में विशेष सरोकार रहेगा।
- भारत-इजरायल के सहयोग से विश्व आतंकवाद की चुनौती से निपटा जा सकता है।
- इजरायल भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है। इजरायल के साथ सामरिक संबंधों की स्थापना से भारत की रूस आदि देशों पर निर्भरता कम हो सकती है।
- भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद फिलीस्तीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र तथा अलग आधारों पर विकसित होंगे।

### अध्ययन का स्वरूप व क्षेत्र –

शोध का कार्यक्षेत्र “भारत और इजरायल संबंध : सुरक्षा एवं कूटनीतिक दृष्टि से एक विश्लेषणात्मक अध्ययन” करना है। भारत-इजरायल के सुरक्षा एवं कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाये गये हैं, उनका विश्लेषण किया गया है, जो निम्नलिखित है –

### सुरक्षा संबंध –

भारत ने सन् 1993 से लेकर अब तक इजरायलके साथबेहद करीबी रक्षा संबंध स्थापित किए है।

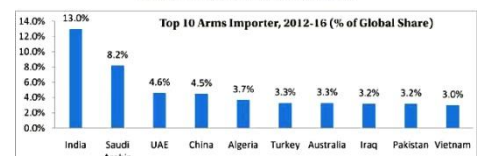
- इजरायल हमारा एक बेहतर रक्षा सहयोगी बनकर उभरा है और लगभग 1500 करोड़ रुपये की रक्षा प्रणाली प्रतिवर्ष उपलब्ध करा रहा है।
- जुलाई 2001 में इजरायल रक्षा मंत्रालय की एक सहयोगी कम्पनी 'इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज' के साथ-साथ अरब डॉलर का एक शस्त्र समझौता भारत ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से किया। इस समझौते के अन्तर्गत इजरायली कंपनी द्वारा लडाकु विमानों, राडार प्रणाली तथा सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेत्रों की आपूर्ति हिन्दुस्तान एयरनॉटिक्स को की जायेगी।
- भारतीय नौ सेना इजरायल की बराक मिसाइलों को प्रयोग में ला रही हैं, जिसे इजरायल की हथियार निर्माता कम्पनी 'राफेल आर्म्स' ने विकसित किया है।
- भारत इजरायल से एंटी राडार अटैक यूएवी अर्थात् मानव रहित विमान खरीद रहा है।
- भारत ने कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन विमानों पर हवाई निगरानी रखने के लिए वर्ष 2007 से 676 करोड़ रु. की लागत से 2 एयरोस्टेट राडार खरीदे है।
- भारतीय वायुसेना इजरायल से 19 लॉ लेवल लाइटवेट राडार खरीद रही है, क्योंकि वायुसेना अपनी सीमा की निगरानी व्यवस्था बढ़ा रही है।
- 15 जुलाई 2020 को भारत और इजरायल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण तीव्रता से हो रहे डिजिटलीकरण सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान साइबर सुरक्षा को सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था। वर्ष 2018 में इजरायल के प्रधानमंत्री बंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान पक्षों के बीच इस विषय को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गये थे।

## भारत इजरायल रक्षा सौदे –

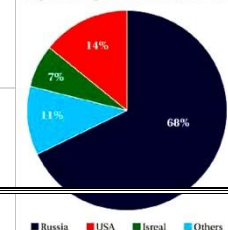
रक्षा खर्च के मामले में भारत छठा सबसे बड़ा देश है, जिसके रक्षा क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत



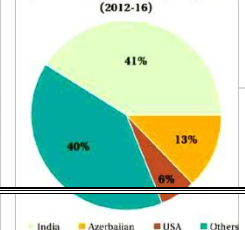
Source: Ministry of Commerce & Industry



Top Arms Exporter to India (2012-16)



Top destination of Arms Export by Israel (2012-16)



Source: Stockholm International Peace Research Institute

हिस्सा है। भारत वर्तमान में रक्षा उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार 2012–2016 की अवधि के दौरान भारत ने वैश्विक हथियारों के आयात का 13 प्रतिशत हिस्सा लिया। इजरायल के लिए भारत अपने हथियारों के निर्यात के लिए शीर्ष स्थान है।

रक्षा इजरायल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों के तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।

- मई 2017 में, IAI को चार भारतीय नौ सेना जहाजों के लिए बराक-8 लॉन्ग-रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए \$630 मिलियन का ठेका दिया गया था।
- मई 2017 में भारतीय वायुसेना द्वारा निर्मित सर्फेस-टू-एयर पायथन और डर्बी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। SPYDER मिसाइल प्रणाली में बढ़ी हुई सटीकता के लिए एक ऑनबोर्ड रडार भी है।
- अप्रैल 2017 में इजरायल ने भारत को मध्यम रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए \$2 मिलियन का रक्षा अनुबंध किया गया। यह सौदा इजरायल के रक्षा उद्योग के इतिहास में एकल सबसे बड़ा अनुबंध था।

### कूटनीतिक संबंध—

1992 में भारत ने इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किये जो कि भारतीय विदेश नीति में ऐतिहासिक परिवर्तन था। भारत ने तेल अबीब में तथा इजरायल ने नई दिल्ली में अपने दूतावास खोले।

- 16 दिसम्बर 1991 को उस समय परिलक्षित हुए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जिओनिज्म (Zionism) को रेसिज्म (Racism) मानने वाले 1975 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए भारत ने इजरायल के पक्ष में मतदान किया।
- 1993 में इजरायल के विदेशमंत्री शीमोन पेरेस ने भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा की।
- 2000 में भारत के गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तथा विदेशमंत्री जसवंत सिंह इजरायल की यात्रा पर गये। दोनों पक्षों ने दीर्घकालीन सहयोग की रूपरेखा के लिये 'एक संयुक्त आयोग' स्थापित करने का निर्णय लिया।

- 31 मई 2000 को राज्यसभा की उपसभापति एवं अंतर्संसदीय संघ की अध्यक्ष श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने इजरायल की संसद नेसेट को सम्बोधित किया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला 3 दिवसीय दौरा इजरायल में 2017 में हुआ तथा 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया।
- संयुक्त राष्ट्र में इजरायल में मानवाधिकार के हनन संबंधी वोट प्रस्ताव के वक्त भारत गैर मौजूद रहा।
- डी-हाइफनेशन कूटनीति –जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की यात्रा पर गए परन्तु इस यात्रा के दौरान वह फिलीस्तीन नहीं गये। इससे पहले भारतीय राजनेता एक साथ दोनो पश्चिमी एशियाई देशों का दौरा करते रहे है। भारत द्वारा इजरायल और फिलीस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नीति को कूटनीति विशेषज्ञों ने 'डी-हाइफनेशन' का नाम दिया।

पिछले कई साल से भारत-इजरायल संबंध काफी बेहतर हुए है लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान संबंध सापेक्ष तौर पर दिख रहे है। दोनो देशों की नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने को लेकर पहले की तुलना में इस समय कहीं ज्यादा है।

### निष्कर्ष –

भारत के इजरायल से संबंध 1993 से ही मधुर रहे हैं, जब इस देश ने तेल अबीब के साथ राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाया था, तब से दोनो देशों के संबंध तेजी से बढ़े हैं। इजरायल ने हमें विकसित सैन्य हार्डवेयर और तकनीक की आपूर्ति की है, जो आसानी से सुलभ नहीं होती है। दोनो देशों ने धरती से आकाश तक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया तथा इस दौरान कृषि , रक्षा, साइबर, सुरक्षा विकास और उड्डयन समेत नौ क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। इजरायल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 'नो कॉन्टेक्ट पॉलिसी' के द्वारा अभिवादन की प्रक्रिया नमस्ते को अपनाया, जो कि भारत-इजरायल के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

#### 1. पुस्तकें –

- 1.1. फड़िया बी.एल., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन 2014
- 1.2. मिश्रा राजेश, भूमण्डलीकरण के दौरे में भारतीय विदेश नीति ISBN: 978-93-S2S4-050-1, गोल्डन पीकॉक-पब्लिकेशन, अगस्त 2016

2. पत्रिकाएँ –

- 2.1. प्रतियोगिता दर्पण
- 2.2. चाणक्य सिविल सर्विसेज, नई दिल्ली
- 2.3. दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, नई दिल्ली

3. वेबसाइट–

- 3.1. [www.pmindia.gov.in](http://www.pmindia.gov.in)
- 3.2. [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
- 3.3. [www.dristias.com](http://www.dristias.com)
- 3.4. [www.jagran.com](http://www.jagran.com)
- 3.5. [www.mea.gov.in](http://www.mea.gov.in)
- 3.6. [blog.my.gov.in](http://blog.my.gov.in)

\*\*\*\*\*